87

दृष्टि The Vision

निबन्ध (ESSAY)

DTVF/17-ESY-E3

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): अनिरुद्ध कुमार

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हां | ✓ | नहीं | |

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address): [redacted]

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date):

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Anirud

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें)

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू०सी०ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिये जाएंगे।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द-संख्या के अनुसार होने चाहियें।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

The ESSAY must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit, as specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

खण्ड A और B में प्रत्येक से एक-एक चुनकर, दो निबंध लिखिये जो प्रत्येक लगभग 1000–1200 शब्दों में हो: 125×2 = 250

Write TWO Essays, choosing ONE from each of the Sections A and B, in about 1000–1200 words each: 125×2 = 250

खण्ड–A / SECTION –A

1. समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा।
   By common endeavor we can raise the country to a new greatness, while a lack of unity will expose us to fresh calamities.
2. कम नकद तथा नकदरहित अर्थव्यवस्था।
   Less cash and cashless economy.
3. यदि आप एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएँ, यदि पाँच वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएँ लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें।
   If you want to plan for a year sow a seed, if you want to plan for five year plant a tree but if you want to plan for a generation educate women.
4. विज्ञान की सीमाएँ जहाँ समाप्त होती हैं अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है।
   Spirituality begins where science ends.

1. समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नयी ऊंचाइयाँ प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का आभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा

———— . ———— . ————

भारत विविधताओं से भरा देश है यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के स्तर पर इतनी विविधतायें हैं जो भारत को एक देश के रूप में नहीं देशों के देश (Nation of Nations) के रूप में स्थापित करती है।

आजादी के बाद भारत गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहा था वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद की आग में भी जल रहा था। वसी समय एक अमेरिकी मैगजीन 'अटलांटिस' में एक लेख छपा था जिसमें बताया गया कि भारत में इतनी समस्यायें है कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित नही हो सकता। यहाँ लोकतंत्र को बनाये रखना संभव नही है। इतनी विविधता को बनाये रखने के लिये भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही (Autocratic) शासन उपयुक्त होगा।

एक तब का भारत था और एक अब का भारत है। भारत ने न केवल अपने लोकतंत्र को ही बनाये नही रखा बरन् विविधता को संरक्षित रखने के साथ उसका पोषण भी किया। हमने सामाजिक क्षेत्र मे काफी प्रगति की। शिक्षा का जो स्तर 1950 के दशक में 18% था उसे 74% तक लेकर आये। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों का बोलबाला था। जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी उसे आज बढ़ाकर हमने 67.8 वर्ष किया। यह हमारी अथक मेहनत व राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही परिणाम था।

आर्थिक क्षेत्र में आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले एक दशकों से हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% के उपर रही है। गरीबी के स्तर को 1950 के 70% के आंकडे से 2011-12 के

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

22.9% (तेंदुलकर समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप) लेकर आये है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को लगातार मजबूती मिली है, जनता के अधिकारों को संरक्षित व पोषित किया गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण को तेज किया गया है। प्रशासन की दक्षता व प्रभाविता में भी सुधार हुआ है।

परन्तु उपरोक्त सफलताओं के बावजूद भी आज भी भारत के समक्ष कई सामाजिक - आर्थिक समस्यायें हैं, खासकर सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की गति पर भी लगाम लगाया है। आज भारतीय समाज की विविधता ही भारत के लिए चुनौती बना हुयी है।

समाज मे जाति विभाजन तो पूर्व से ही रहा है परन्तु वर्तमान में इसकी तीव्रता बढ़ी है। आज जातियों के बीच संघर्ष बढ़े है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर निम्न जातियाँ जहाँ सत्ता के विभिन्न पक्षों व स्तरों पर अपने को काबिज कर रही है वहीं उच्च जातियाँ अपने सत्ता के बँटवारे को लेकर तनाव महसूस कर रही है। इसी के साथ ही निम्न जातियों का पिछड़ापन भी उन्हें सरकार व प्रशासन के प्रति आंदोलित होने को बाध्य कर रहा है। यही कारण है कि जातीय संघर्ष, नक्सलवाद आदि तेजी से बढ़े है। बिहार मे रणवीर सेना व माओइस्ट कम्यूनिस्ट सेंटर (MCC) के बीच खूनी संघर्ष को कौन भूला

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

सकता है।

केवल जाति ही नहीं धर्म भी आज भारतीय समाज के समक्ष चुनौती बना हुआ है। खासकर हिंदू- मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त ऐतिहासिक अविश्वास गुजरात दंगों, मुजफ्फरनगर दंगों आदि के रूप में परिलक्षित होता दिख रहा है। इसने समाज में विभाजन की खाई को गहरा किया है। प्रसिद्ध विद्वान सालिग हेरिसन मानते है कि "भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति व धर्म ही सबसे बड़ी बाधायें है जिन्हें तोड़ना कठिन है।"

जाति व धर्म की तरह भाषायी विवाद भी ऐसा मुद्दा रहा है जिसने लगभग एक शताब्दी से भारत को भयभीत करके रखा है। स्वतंत्रता के बाद से ही भाषा को लेकर कई आंदोलन हुये, खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने व हिन्दी थोपे जाने के विरोध में (जनमत) को उग्र विरोध प्रदर्शन के लिये प्रोत्साहित किया गया। आज भी भाषा एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाली ही मे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगाली (बंगला) भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य बनाये जाने को तीव्र विरोध प्रदर्शन हुये जिसमें जान-माल की व्यापक क्षति हुई।

समन्वित प्रयास
दलित आदि
राजनीतिक एवं आर्थिक
विकेन्द्रीकरण सशक्तिकरण
इत्यादि की

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

इन सभी नृजातीय तत्वों में व्याप्त विविधता ने भारतीय समाज में संघर्ष को तेज किया है। आज जहाँ समान सिविल संहिता (UCC) की मांग को लेकर बहुसंख्यक समुदायों में आक्रोश है तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में भय है कि कहीं इससे उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान (identity) खो नहीं जाएगी। इसी तरह पिछले कुछ समय में 'गौ' भी एक प्रमुख विषय बना है। गौ रक्षा के नाम बने cow vigilante समूहों द्वारा होने वाली हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता।

इसी तरह कश्मीर के सन्दर्भ में धारा (art) 370 को खत्म किये जाने की मांग को भी तेजी से जन समर्थन मिला है। कई लोग जो वास्तव में अनु० 370 की महत्ता को नहीं जानते हैं, वे भी इसके सन्दर्भ में हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस तरह के मसलों पर जनमत का उग्र होना और तार्किक होकर पर्याप्त विचार विमर्श के साथ निर्णय न लेना भी कश्मीरियों के मन में भारत के प्रति अलगाव बढ़ा रहा है।

केवल कश्मीर ही नहीं देश का उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (North-East Region) भी अपने को भारत का अंग नहीं समझता। इसका मुख्य कारण उनका पिछड़ापन व उनके साथ होने वाला भेदभाव है। आज भी उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लोगों को नेपाली, पहाड़ी, चिंकी आदि नामों से पुकारा जाता है जो उनमें शेष भारत के प्रति क्षोभ पैदा करता है।

विभिन्न समुदायों के लिए प्रशासनिक प्रयास को लिखें

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय महालनोबिस मॉडल पेश किया गया था जिसमें यह संकल्पना व्यक्त की गयी थी कि – " समय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बने पहचान विलुप्त होते जायेंगे व विकास धर्मनिरपेक्ष गति से आगे बढ़ेगा।" परन्तु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। शायद हम उस राष्ट्र की संकल्पना से दूर जा रहे हैं जिसका स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज जरूरत है कि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विविधता को प्रोत्साहित व संरक्षित करे।

जाति विभेदित समाज को किसी भी स्थिति में आदर्श समाज नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में समानता का लक्ष्य रखा। आरक्षण के सन्दर्भ में सकारात्मक भेदभाव की नीति (Positive discrimination Policy) अपनायी। आज भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार के प्रयास कर रही है। आज ये रोजगार ढूंढने वाले न बनकर रहे बल्कि रोजगार को पैदा करने वाले बने, इसके लिए 'दलित कैपिटलिज्म' को प्रोत्साहित कर इनमें उद्यमिता का विकास किया जा रहा है।

इसी तरह विकास की धारा में पिछड़े बने रहे जनजाति समुदाय को भी मुख्य धारा में लाना होगा, उनके जल-जंगल-जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी, उनकी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना होगा,

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो गरीबी, भूखमरी, नक्सलवाद, जातीय संघर्ष जैसे संकट प्रभावहीन हो जायेंगे।

आज जरूरत है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) की जगह समावेशी राष्ट्रवाद (inclusive Nationalism) की संकल्पना को बल प्रदान करें। ऐसी राष्ट्रवादी भावना जिसमें के सभी समूहों व वर्गों की भागीदारी हो। नाजीवाद व फासीवाद भी राष्ट्रवाद के ही रूप थे पर घिनौने रूप थे वहीं गांधी व नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद था क्योंकि ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त कराने का काम किसी एक समूह या एक जाति या किसी एक धर्म ने नहीं वरन् सभी समूहों, सभी जातियों व सभी धर्मों ने मिलकर किया था।

आज भी हमारे समक्ष ब्रिटिश शासन की तरह ही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि विघटनकारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं जिनसे भारत पिछले 70 वर्षों से आजाद होने का प्रयास कर रहा है परन्तु ये प्रयास तब तक पूरे नहीं हो पायेंगे जब तक हम अपने को एक विशिष्ट जाति या एक विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषायी समूह के सदस्य मानते रहेंगे। हमें इन संकीर्ण मानसिकताओं से

(Margin remarks: नीति-निर्माण में आदर्शवाद की उपयोगिता, व्यावहारिकता, आवश्यकता; प्रभावित प्रयासों से सफलता, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(Remark: शब्द सीमा को पूरा करने का प्रयास करें)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

ऊपर उठकर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने को पहचानना होगा। इस समय मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता 'Where the mind is without fear' की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं—

"जहाँ दिलो दिमाग पर खौफ का साया न हो
जहाँ सर शर्म से झुके हों, कोई सर शर्म से झुकाया न हो,
जहाँ ज्ञान को बंधनों में न बांधे इंसान,
जहाँ छोटी-छोटी सरहदों में न बँटा हो जहान,
हे परमपिता परमेश्वर, भारत को एक गहरी नींद से जगाकर एक नवयुग में उद्धार करो।"

(Remarks: यह प्रकरण प्रश्न की मांग से बहुत अलग है; कृपया उत्तर ऐसे लिखें कि निबंध के लगभग सभी आयामों को प्रस्तुत करें) 32

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

खण्ड–B / SECTION –B

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

1. एक राष्ट्र : एक निर्वाचन
   One nation: One election.
2. भारत में डिजिटल अंतराल : ग्राम्य रूपांतरण में अवरोध
   Digital divide in India: A roadblock to rural transformation.
3. कायांतरित भारत : नवीन भारत
   Transforming India: New India.
4. निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है।
   A close neighbour is better than distant relative.

एक राष्ट्र : एक निर्वाचन

निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तम्भ माना जाता है। निर्वाचन को तो 'मतपत्र द्वारा क्रांति' की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है – 'एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है।" (मॉलकम एक्स का कथन)

भारतीय लोकतंत्र में एक वार्ष संघीय तथा निर्वाचन वाली राज्यों के चुनावों की पुष्टि लिखें

वैसे तो भारत मे चुनाव प्रक्रिया काफी सफल रही है तथा समय समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं परन्तु पिछले कुछ समय से एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है और वह है 'संसदों (लोकसभा) व सभी राज्य विधानमण्डलों के चुनाव एक साथ कराना।' इस मुद्दे पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री व भूतपूर्व राष्ट्रपति ने काफी बल दिया है। अतः ऐसे में यह विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि 'एक निर्वाचन' की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या इसे लागू करना आसान होगा, किन-किन चुनौतियों का इसे

Copyright – Drishti The Vision Foundation

सामना करना पड़ेगा, साथ ही क्या यही सुधार निर्वाचन प्रक्रिया में चल रहे समस्याओं व राजनीति की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है या कुछ अन्य उपाय भी करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर इस लेख में विचार विमर्श किया जायेगा।

सर्वप्रथम यह बताते चलें कि 'एक निर्वाचन' का सिद्धान्त कोई नया नहीं है। भारत के अलावा भी कई देशों में इसका प्रचलन है। भारत में विधि आयोग (Law Commission) ने भी कई बार इस मुद्दे पर विचार किया है। संसद की कई समितियों ने भी इस संबंध में अनुशंसा दी है। वास्तव में भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या (1.3 अरब) रहती है, उसमें से भी लगभग एक-चौथाई से ज्यादा निरक्षर हैं साथ ही समाज में उच्च-नीच का भेदभाव इतना गहरा है कि एक सफल चुनाव सम्भव करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है।

सामान्यतः किसी लोकतंत्र में सरकार की अवधि 5 साल की होती है परन्तु पाया गया है कि सरकारें औसतन चार साल ही काम करती हैं क्योंकि चुनावी साल में सामान्यतः सरकार के सभी कामकाज ठप्प रहते हैं व सरकारी तंत्र चुनावी प्रचार की व्यवस्था व चुनाव को सफल क्रियान्वित कराने की व्यवस्था में ही लगा रहता है। चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में या देश में (लोकसभा चुनाव के समय) MCC (Model code of conduct) लागू हो जाता है। यह MCC चुनाव के परिणाम

Copyright – Drishti The Vision Foundation

की घोषणा तक लागू रहता है। इस दौरान सरकार कोई नये विकास के कार्य शुरू नहीं कर सकती साथ ही पुराने कार्य भी प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव में व्यस्त रहने से ठप्प पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चुनाव के समय MCC की अवधि ढाई से तीन माह तक की होती है अतः इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं से महरूम रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता।

निरंतर चुनावों के फलस्वरूप विकास कार्यों को होने वाले नुकसान तथा सामान्य जन को होने वाली परेशानियों राष्ट्र को अन्य परेशानियों का उल्लेख भी

कभी भी पाया गया है कि चुनावी साल में सरकार चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण सरकार backsheet पर चली जाती है व प्रशासन (नौकरशाही) frontsheet पर आ जाती है। यह लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध है क्योंकि राज्य का शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलायी जानी चाहिए न कि सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाही से।

इसके साथ ही चुनाव के अलग-अलग होने पर धन का खर्च भी ज्यादा होता है साथ ही Bogus voting की समस्या भी उभरती है क्योंकि एक वोटर अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों में नकली पहचान पत्र से वोट करने में सफल हो जाता है यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है।

अतः इन्हीं चुनौतियों के सन्दर्भ में 'एक राष्ट्र : एक निर्वाचन' का सिद्धान्त दिया जाता है। एक ही साथ

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की अनुशंसा की जाती है। इससे लगातार चलने वाले चुनावों से होने वाले विकास प्रक्रिया की बाधा भी घटेगी और साथ ही प्रशासन भी चुनावी व्यवस्था से जल्दी मुक्त होकर सामान्य स्थिति के संचालन में योगदान कर पायेगा। इसके साथ ही इससे voter turnout भी बढ़ने की संभावना है इसके अलावा bogus voting जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। एक साथ होने वाले चुनावों से चुनाव में धन-बल का प्रयोग भी घटने की संभावना है।

परन्तु 'एक निर्वाचन' उपरोक्त लाभों के साथ कई चुनौतियों से भी भरा है सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या इस प्रक्रिया द्वारा बनी हुई सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने में सक्षम होगी? अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भंग किया गया तो फिर क्या चुनाव के अगले आने वाले चुनावी साल तक इंतजार करना पड़ेगा और तब तक सरकार का संचालन कौन करेगा? साथ ही अगर राष्ट्रपति/राज्यपाल सरकार के ही कहने समय से पूर्व लोकसभा/विधानसभा को भंग कर दे तो सरकार का संचालन कैसे होगा।

इस तरह इस व्यवस्था में पूरी संसदीय प्रणाली में ही व्यापक बदलाव करने होंगे। साथ ही यह व्यावहारिक रूप से भी सफल होने की संभावनाओं

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

को खारिज करता है। भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी की जरूरत होगी जो न तो उपलब्ध हो पाएगी और न ही चुनाव आयोग ऐसा प्रबंधन कर पाने में सक्षम होगा। अगर किसी तरह प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी का इंतजाम भी किया गया तो देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए इस समय गंभीर चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। अलगाववादी तत्व इस स्थिति का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे।

S.Y. कुरैशी ने कहा, लगातार चुनाव के कारण जमीनी स्तर पर राजनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है इसे भी कहें

अगर इसकी व्यवहारिकता पर और विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उत्तरप्रदेश जैसे एक राज्य में ही चुनाव कराने में 8-9 चरणों में चुनाव संपन्न कराने पड़ते हैं तो फिर तो भारत में 29 राज्य व 2 केन्द्रशासित राज्य (जिनमें विधानसभा है- दिल्ली व पांडिचेरी) हैं उनमें एक साथ चुनाव कैसे कराये जा सकते हैं।

इसके अलावा हमें अपने नागरिकों के शैक्षिक स्तर को भी देखना होगा। क्योंकि एक डर यह भी माना जाता है कि एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दे आपस में मिश्रित हो जायेंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अलग मुद्दे होते हैं व जब राष्ट्रीय चुनाव (लोकसभा का) होता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरणत: 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता दल को 40 में से 38 सीटें मिली पर वहीं 2016 में हुये विधानसभा चुनाव में इसे बहुत कम समर्थन मिला। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय था अत: पर्याप्त जनसमर्थन नहीं मिला।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

अतः एक साथ चुनाव कराने पर क्या जनता इतनी जागरूक है, इतना जनता का मानसिक स्तर है कि वह क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से अलग कर देख सके।

कुल मिलाकर 'एक निर्वाचन' की व्यवहारिकता काफी जटिल है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस माँग का समर्थन नहीं किया है। हाँ, इस दिशा में कुछ और सुधार किये जा सकते हैं जैसे जिन राज्यों में चुनाव 6 महीनों के अंतराल पर होने हों उनमें एक साथ चुनाव कराये जायें। इसी तरह जिन राज्यों के चुनाव के लोकसभा के चुनावी साल में पड़ रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव के साथ ही जोड़कर चुनाव कराये जा सकते हैं। हालाँकि ऐसा प्रयोग चुनाव आयोग ने किया है व 2014 के लोकसभा चुनाव के समय इसका सफल परीक्षण किया गया है तथा इसके बाद भी राज्यों के चुनाव club करके कराये जा रहे हैं।

बेहतर चुनावी कार्यान्वयन के लिए अन्य चुनावी सुधारों की भी उल्लेख करें।

अतः 'एक राष्ट्र: एक निर्वाचन' की दिशा में अभी पर्याप्त विचार विमर्श की जरूरत है, विशेषज्ञों की राय भी जाननी होगी साथ ही आम जनता और चुनाव आयोग का भी विश्वास हासिल करना होगा। वेंकटचेलैया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा पर गठित 'संविधान समीक्षा आयोग' ने भी माना था-

"चुनावी व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की बजाए हमें वर्तमान व्यवस्था को ही अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देनी होगी ताकि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा सके।"

आज जरूरत है कि चुनावी व्यवस्था की शुचिता को पुनर्बहाल किया जाये। चुनाव के द्वारा राजनीति में बढ़ रहे पूंजीपति व अपराधी तत्वों के ऊपर लगाम लगानी होगी। राजनीतिक दलों में भी व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद आदि पर लगाम लगाते हुये आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना होगा। तभी हम शान से कह पायेंगे -

"सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्ताँ हमारा।"

55

Copyright – Drishti The Vision Foundation